दैनिक न्याय साक्षी

अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्यायसाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 || Postal Registration No-055/Raigarh DN CG || रायगढ़, बुधवार 19 जनवरी 2022 || पृष्ठ-4, मूल्य 3 रूपए || वर्ष-04, अंक- 113

महत्वपूर्ण एवं खास

सेना ने प्राइवेट सेक्टर से 96 करोड़ रुपए का करार किया

नई दिल्ली (आरएनएस)। भारतीय सेना ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने की दिशा में मंगलवार को अहम कदम उठाया। सेना ने मेन्यूवेरेबल एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट के लिए मेक-द्वितीय के तहत एनाड्रन सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ 96 करोड़ रुपये के पहले करार पर हस्ताक्षर किया। डिफेंस प्रोडक्शन इंडिया ने ट्वीट करके इस समझौते की जानकारी दी। ट्वीट में कहा गया कि भारतीय सेना ने मेन्यूवेरेबल एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट के लिए मेक-द्वितीय के तहत एनाड्रन सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ करार पर हस्ताक्षर किया है। यह समझौता 96 करोड़ रुपये का है। सेना प्रमुख नरवणे ने 15 जनवरी को 74वें सेना दिवस के अवसर पर सेना के एक कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश आत्मनिर्भर सेना की दिशा में प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि आईआईटी सहित भारतीय शैक्षणिक संस्थानों के संयुक्त प्रयासों से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), ब्लॉकचैन, क्वांटम कंप्यूटिंग, मानव रहित सिस्टम, निर्देशित ऊर्जा हथियार और स्वर्ण ड्रोन जैसी कई नई तकनीकों का विकास किया जा रहा है। सेना प्रमुख ने कहाकि कोविड महामारी के दौरान पड़ोसी देशों के साथ हमारा आपसी सहयोग और बढ़ा है। संयुक्त राष्ट्र पीसकीपिंग ऑपरेशन में भारतीय सेना का महत्वपूर्ण योगदान हमेशा रहा है। हमारे सेना के आज भी 5,000 से ज्यादा सैनिक विभिन्न पीसकीपिंग मिशन में तैनात हैं, जो देश को अलग पहचान दे रहे हैं।

लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे उप सेनाध्यक्ष नियुक्त

नई दिल्ली (आरएनएस)। सरकार ने मंगलवार को लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को उप सेना प्रमुख नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। ले. जन. पांडे अभी सेना की पूर्वी कमान के कमांडर हैं। ले. जनरल मनोज पांडे ने 1 जून को पूर्वी सेना कमान के नए कमांडर (जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ) के रूप में कार्यभार संभाला था। यह कमान पूर्वोत्तर राज्यों सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश क्षेत्रों में चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) की रक्षा के लिए तैनात है। इसका मुख्यालय कोलकाता में है। लेफ्टिनेंट जनरल पांडे पूर्वी कमान के प्रमुख बनने से पहले अंडमान एवं निकोबार कमान के कमांडर-इन-चीफ थे।

पंजाब में कई स्थानों पर ईडी ने की छापेमारी, अवैध रेत खनन मामला

नई दिल्ली (आरएनएस)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गैरकानूनी तरीके से रेत का खनन करने में शामिल कम्पनियों के खिलाफ धन शोधन की जांच के तहत पंजाब में कई स्थानों पर मंगलवार को छापेमारी की। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सीमावर्ती राज्य में कम से कम 10 से 12 स्थानों पर छापेमारी की जा रही है और संघीय एजेंसी के अधिकारी धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत कार्रवाई कर रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि राजनीतिक संपर्क रखने वाले कुछ लोगों के ठिकानों पर भी छापेमारी की जा रही है। गौरतलब है कि पंजाब की 117 सदस्यीय विधानसभा के लिए 20 फरवरी को मतदान होना है।

पाकिस्तान में अपराधियों के साथ मुठभेड़ , पुलिसकर्मी समेत तीन की मौत

इस्लामाबाद। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी और दो हथियारबंद लुटेरे मारे गये जबकि चार अन्य घायल हो गये। पुलिस सूत्रों ने बताया कि घटना बीती देर रात उस समय हुई , जब पुलिस की टीम ने नियमित जांच के दौरान मोटरसाइकिल पर सवार दो लोगों को रुकने का संकेत दिया। इसी दौरान मोटरसाइकिल सवार में से एक ने पिस्तौल निकालकर पुलिस पर गोलियां चला दीं। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई में गोलियां चलायी। दोनों तरफ से गोलीबारी में एक पुलिस कर्मी की मौत हो गयी और दो अन्य घायल हो गये। वहीं दो अपराधी मौके पर ही मारे गये। मौके पर पहुंचे पुलिस और बचाव दल ने घायलों को शहर के नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है।

बांग्लादेश सीमा पर 82 फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस जब्त, बीएसएफ ने की बड़ी कार्रवाई

नई दिल्ली (आरएनएस)। भारत-बांग्लादेश की सीमा पर बड़ी कार्रवाई करते हुए बीएसएफ ने 82 फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस जब्त किए हैं। यह सब तब हुआ जब बीएसएफ की एक औचक जांच में पाया कि कम से कम 82 ट्रक चालक नकली ड्राइविंग लाइसेंस का प्रयोग कर रहे थे। ये सभी ड्राइविंग लाइसेंस बांग्लादेश से आने-जाने वाले ट्रकों के लिए प्रयोग में लाए जा रहे थे।

बीएसएफ के एक सीनियर अधिकारी ने यह जानकारी देते हुए बताया कि सीमा सुरक्षा बल को इनपुट मिले थे कि कुछ ड्राइवर भारत और बांग्लादेश के बीच माल के निर्यात और आयात में सोने-चांदी, फेसेडिल सिरप, ड्रग्स आदि की तस्करी जैसे सीमा पार अपराधों में शामिल हैं। इसके बाद औचक जांच की गई और 16-17 जनवरी को ड्राइवरों के पास से कुल 82 फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस मिले हैं। यह सभी जब्त किए गए लाइसेंस बीएसएफ ने सीमा शुल्क विभाग को सौंप दिए हैं। यह मामला सामने आने के बाद जांच के लिए मामला दर्ज किया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय सीमा शुल्क और भूमि बंदरगाह प्राधिकरण को सूचित किया गया है कि फर्जी लाइसेंस पर चलने वाले ड्राइवरों को अनुमति नहीं दी जा सकती है। प्रवक्ता ने आगे कहा कि फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस वाले किसी भी ड्राइवर को किसी भी कीमत पर ट्रकों को चलाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है क्योंकि ऐसे ड्राइवर ड्राइविंग लाइसेंस के आधार पर सीमा शुल्क विभाग से नकली पास प्राप्त करते हैं, जिस पर बीएसएफ ट्रकों को अंदर जाने की अनुमति देता है।

भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार को सुचारू रूप से चलाने के लिए बीएसएफ ने सीमा पार बनगांव ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन को स्थायी संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) का पालन करने के लिए भी सूचित किया है ताकि सुरक्षा और हितों से समझौता न हो। पेट्रापोल आईसीपी दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा भूमि चेकपोस्ट है, जो भारत और बांग्लादेश के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ कोलकाता से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।

पेट्रापोल (भारत)-बेनापोल (बांग्लादेश) व्यापार और यात्री आवाजाही के मामले में दोनों देशों के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु है। भारत और बांग्लादेश के बीच लगभग 30 प्रतिशत भूमि आधारित व्यापार यहीं से होता है। इसे फरवरी 2016 में चालू किया गया था, पेट्रापोल आईसीपी से यात्रियों की आवाजाही की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसमें से हर साल औसतन 22 लाख लोग सीमा चौकी को पार करते हैं। बता दें कि आइसीपी पेट्रापोल के जरिए हाल के दिनों में तस्करी गतिविधियों में वृद्धि की सूचनाएं मिलती रही हैं। इसी कारण बीएसएफ ने अपनी निगरानी और सतर्कता तंत्रों को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। हाल ही में चार जनवरी को, एक ट्रांसपोर्टर से करीब डेढ़ करोड़ रुपये का तस्करी का सोना जब्त किया गया था, जब वह आईसीपी पेट्रापोल में बीएसएफ के सुरक्षा घेरे से बाइक पर भागने की कोशिश कर रहा था। बाद में पता चला कि यह सोना बांग्लादेश से आयात करने वाले ट्रक के अंदर छिपाकर बांग्लादेश से तस्करी कर लाया गया था।

देश में 55 लाख से ज्यादा हेल्थकेयर-फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगी बूस्टर डोज

नई दिल्ली (आरएनएस)। देश में अब तक 55 लाख से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 साल व उससे ज्यादा उम्र के लोगों को कोरोना वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज लग गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने मंगलवार को ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जो लोग प्रिकॉशन डोज के लिए योग्य हैं, वैक्सीनेशन जरूर कराएं।

भारत ने स्वास्थ्य कर्मियों, चुनाव ड्यूटी के लिए तैनात कर्मियों सहित फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 साल व उससे अधिक उम्र के लोगों को कोविड-19 वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज लगाना शुरू किया। कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वैरिएंट से बढ़ते संक्रमण के बीच 10 जनवरी से प्रिकॉशन डोज लगाने का फैसला किया गया।

देश में कोरोना वैक्सीनेशन 16 जनवरी, 2021 से शुरू- वहीं, बीते 24 घंटे में कोरोना वैक्सीन की 80 लाख से अधिक डोज लगाई गई। इस तरह देश में अब तक कोरोना टीके की 158 करोड़ से ज्यादा खुराक लगाई जा चुकी है। देश भर में टीकाकरण अभियान 16 जनवरी, 2021 को शुरू किया गया, जिसमें स्वास्थ्य कर्मियों को पहले चरण में टीका लगाया गया था। वहीं, फ्रंटलाइन वर्कर्स का वैक्सीनेशन पिछले साल 2 फरवरी से शुरू हुआ था।

15-18 साल के किशोरों का 3 जनवरी से टीकाकरण जारी- 15-18 साल के किशोरों का 3 जनवरी से टीकाकरण जारीकोरोना टीकाकरण का अगला चरण 1 मार्च से 60 साल से अधिक उम्र के लोगों और 45 वर्ष व उससे अधिक आयु के लोगों के लिए शर्तों के साथ शुरू हुआ। देश में 1 अप्रैल, 2021 से 45 साल से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए टीकाकरण शुरू किया। इसके बाद सरकार ने 1 मई से 18 साल से ऊपर के सभी लोगों का टीकाकरण शुरू किया। वहीं, 15-18 साल की उम्र के किशोरों के लिए इस साल 3 जनवरी से कोविड-19 टीकाकरण का अगला चरण शुरू हो गया है।

पीएम को टारगेट कर साजिश रच रहे आतंकी, खुफिया एजेंसियों को मिला अलर्ट

नई दिल्ली (आरएनएस)। खुफिया एजेंसियों को गणतंत्र दिवस पर संभावित आतंकी साजिश के बारे में अलर्ट मिला है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की जान को खतरा बताया गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, नौ पन्नों की खुफिया जानकारी में पीएम मोदी और उन हस्तियों के लिए खतरा बताया गया है जो भारत के 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होंगे। गणतंत्र दिवस पर पांच मध्य एशियाई देशों- कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उजबेकिस्तान के नेताओं को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किए जाने की संभावना है। नोट में बताया गया है कि यह खतरा पाकिस्तान/अफगानिस्तान-पाकिस्तान के बाहर स्थित गुटों से है।

साजिश में जुटे हैं ये आतंकी संगठन- रिपोर्ट के मुताबिक आतंकी संगठनों का उद्देश्य बड़ी हस्तियों को टारगेट करना, सार्वजनिक सभाओं, महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों और भीड़-भाड़ वाले इलाकों में अशांति फैलाना है। ड्रोन से भी हमले की कोशिश की जा सकती है। इनपुट में कहा गया है कि आतंकी खतरे के पीछे लश्कर-ए-तैयबा, द रेजिस्टेंस फोर्स, जैश-ए-मोहम्मद, हरकत-उल-मुजाहिदीन और हिज्ब-उल-मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठन हैं। वहीं खुफिया इनपुट में कहा गया है कि पाकिस्तान में स्थित खालिस्तानी समूह भी पंजाब में आतंक फैलाने के लिए कैडरों को जुटा रहे हैं।

सपा की मान्यता रद्द करने की मांग वाली अर्जी पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

» कैराना से नाहिद हसन की उम्मीदवारी पर घिरे हैं अखिलेश

नई दिल्ली (आरएनएस)। उम्मीदवार के आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी न देने का आरोप लगाते हुए सपा की मान्यता खत्म करने की मांग वाली अर्जी पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट सहमत हो गया है। यह जनहित याचिका वकील अश्विनी उपाध्याय की ओर से दायर की गई है। याचिकाकर्ता वकील अश्विनी उपाध्याय ने चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच से इस याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया।

उपाध्याय ने अपनी अर्जी में कहा था कि यूपी में चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ऐसे में आपराधिक लोगों को रोकने के लिए इस अर्जी पर तत्काल सुनवाई किए जाने की जरूरत है। याचिकाकर्ता ने गैंगस्टर ऐक्ट में जेल गए सपा के प्रत्याशी रहे नाहिद हसन का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सपा ने आपराधिक रिकॉर्ड वाले नाहिद हसन को प्रत्याशी घोषित कर दिया। यही नहीं चुनाव आयोग के आदेश के मुताबिक उसके बारे में अपनी वेबसाइट, सोशल मीडिया, प्रिंट एवं टीवी मीडिया पर जानकारी भी नहीं दी। यह आयोग और सुप्रीम कोर्ट के दिए गए फैसले की अवमानना है। ऐसे में समाजवादी पार्टी समेत ऐसे सभी दलों का पंजीकरण खत्म होना चाहिए, जो अपने उम्मीदवारों के आपराधिक इतिहास का खुलासा नहीं करते हैं। उपाध्याय ने अपनी याचिका में कहा कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कैराना से सपा ने नाहिद हसन को चुनावी मैदान में उतारने घोषणा की है। उनका आरोप है कि हसन एक गैंगस्टर है लेकिन सपा ने इस उम्मीदवार के आपराधिक रिकॉर्ड को समाचार पत्र, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया में प्रकाशित-प्रसारित नहीं किया। यही नहीं उनके चयन की वजह भी नहीं बताई।

कोरोना की तीसरी लहर पड़ी धीमी, दैनिक मामलों में कमी शुरू : 24 घंटे में 238018 नए मामले, 310 लोगों की मौत

» सक्रीय मरीजों का आंकड़ा 16 लाख के पार

नई दिल्ली (आरएनएस)। देश में पिछले दो दिनों से लगातार दैनिक संक्रमण के मामलों में आ रही गिरावट से संकेत मिल रहे हैं कि कोरोना की तीसरी लहर के पीक का समय गुजर गया है, जिसके कारण दैनिक मामलों में कमी देखी जा रही है। जबकि ओमिक्रॉन में तेजी देखी जा रही है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मंगलवार को जारी आंकड़ो के अनुसार पिछले दो दिन से लगातार संक्रमण के दैनिक मामले कम हुए हैं। पिछले 24 घंटे में देशभर में कोरोना के 2,38,018 नए मामले सामने

आए हैं, जो सोमवार के मुकाबले 20 हजार कम हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 1,57,421 संक्रमित ठीक हुए हैं तो 310 की मौत हुई है। लेकिन जारी आंकड़ों के अनुसार देश में अब कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 17,26,628 हो गई है, जो कुल मामलों का 4.62 फीसदी है। फिलहाल देश भर में रिकवरी रेट 94.09 फीसदी है। वहीं दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में जिस तरह से कोरोना के नए केसों की ग्रोथ में गिरावट देखने को मिल रही है, वह राहत की बात है।

देश में ओमिक्रॉन के 8891 मामले- मंत्रालय के अनुसार कोरोना वायरस के वैरिएंट ओमिक्रॉन से संक्रमण के 8891 नए मामलों की पुष्टि हुई है। एक दिन पहले की तुलना में ओमिक्रॉन वैरिएंट से संक्रमण में 8.31 फीसदी की तेजी आई है। पूरी दुनिया के लिए संकट का सबब बना ओमिक्रॉन भारत के सभी राज्यों में पहुंच चुका है। इनमें से सबसे ज्यादा 63 नए मामले केरल में ओमिक्रॉन वैरिएंट के सामने आए, जहां अब तक इस वैरिएंट के मरीजों की संख्या 591 हो गई है। नए मरीजों में से चार का संबंध तमिलनाडु से है, जो विभिन्न देशों से केरल आए हैं। 36 कम जोखिम वाले और नौ उच्च जोखिम वाले देशों से आए हैं। नौ लोग इनके संपर्क में आकर संक्रमित हुए हैं।

वैक्सीनेशन 158.76 करोड़ के पार

मंत्रालय के अनुसार बीते 24 घंटे में कोरोना वैक्सीन की 80 लाख से अधिक डोज लगाई गई। इस तरह देश में अब तक कोरोना टीके की 158.76 करोड़ से ज्यादा खुराक लगाई जा चुकी है। इसमें 91,71,66,516 पहली डोज और 66,50,00,156 दूसरी डोज दी जा चुकी है। जबकि 55,07,939 बूस्टर डोज के रूप में भी लगाई जा चुकी है, जिसकी शुरूआत दस जनवरी से की गई थी। वहीं तीन जनवरी से शुरू हुए 15-17 साल आयु वर्ग के किशोरों को अब तक 3.70 करोड़ से ज्यादा डोज लगाई जा चुकी है।

केंद्र ने राज्यों को पत्र भेजकर कोरोना जांच की रफ्तार बढ़ाने को कहा

नई दिल्ली (आरएनएस)। देश इस समय कोरोना वायरस महामारी की तीसरी लहर का सामना कर रहा है और इस दौरान कोरोना वायरस की जांच में ही कमी आती देखी जा रही है। इसे लेकर केंद्र सरकार ने सख्त रुख अपनाया है और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस संबंध में एक पत्र लिखा है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से लिखे गए इस पत्र में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस मामले पर तुरंत ध्यान देने और रणनीतिक तरीके से कोरोना जांच की संख्या बढ़ाने का निर्देश दिया है। पत्र में कहा गया है कि महामारी के प्रसार के सही रिकॉर्ड लिए ऐसा करना जरूरी है। यह पत्र स्वास्थ्य मंत्रालय की अतिरिक्त सचिव आरती आहूजा ने लिखा है और कहा है कि आईसीएमआर के पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों से पता चलता है कि देश के खई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना जांच में गिरावट आई है। इस रुख को तत्काल बदलने की जरूरत है।

एनडीए परीक्षा 2022 के लिए महिलाओं की संख्या सीमित करने का मामला

» सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार से मांगा जवाब

नई दिल्ली (आरएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मंगलवार को कहा कि वह स्पष्ट करे कि आखिर उसके आदेश के बावजूद वर्ष 2022 के लिए भी पिछले साल के बराबर ही राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए) में महिला उम्मीदवारों की सीट 19 ही क्यों सीमित की गई। शीर्ष अदालत ने केंद्र से कहा कि वह राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज (आरआईएमसी) और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल (आरएमएस) में प्रवेश के लिए आयोजित एनडीए परीक्षा 2021 में महिलाओं सहित कुल

उम्मीदवारों की संख्या से जुड़े आंकड़े न्यायालय में पेश किये जाएं। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति एमएम सुंद्रेश की पीठ ने केंद्र की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से कहा कि सरकार को बताना होगा कि यूपीएससी की अधिसूचना के मुताबिक आखिर क्यों वर्ष 2022 के लिए महिलाओं की संख्या 19 तय की गई। पीठ ने कहा कि यह साल 2021 के आंकड़ों के बराबर हैं। पिछले साल आपने कहा था कि अवसंरचना की कमी की वजह से महिलाओं का कम प्रवेश लिया जा रहा है। अब आपने फिर साल 2022 के लिए महिलाओं उम्मीदवारों के लिए उतनी ही संख्या का प्रस्ताव किया है।

आपने ये आंकड़े क्यों तय किए? आपको यह स्पष्ट करना होगा। 19 सीट हमेशा के लिए नहीं होनी चाहिए। यह केवल एक तदर्थ उपाय है। शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार को मामले में हलफनामा दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया और बाकी पक्षकारों को उसके बाद दो सप्ताह में अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। पीठ ने इसके साथ ही मामले की सुनवाई छह मार्च के लिए सूचीबद्ध कर दी। इससे पहले, याचिकाकर्ता कुश कालरा की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता चिन्मॉय प्रदीप शर्मा ने बताया कि उन्होंने अतिरिक्त हलफनामा दाखिल किया है जिसमें उल्लेख है कि 14 नवंबर 2021 को हुई एनडीए की परीक्षा में 8,009 प्रत्याशी ने सेवा चयन बोर्ड परीक्षा और चिकित्सा जांच के लिए उत्तीर्ण हुए जिनमें से 1,002 उम्मीदवार महिलाएं हैं जबकि 7,007 प्रत्याशी पुरुष हैं। उन्होंने कहा कि संघ लोकसेवा आयोग (यूपीएससी) के विज्ञापन और सरकार द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक वर्ष 2021 के एनडीए-द्यद्य में एनडीए 400 कैडेट को लेगा। शर्मा ने कहा कि इनमें से 10 महिलाओं सहित 208 उम्मीदवार सेना में लिए जाएंगे। नौसेना तीन महिलाओं के साथ 42 उम्मीदवारों को लेगी।

भारतीय वायुसेना भी छह महिलाओं के साथ 120 उम्मीदवारों को प्रवेश देगी। इस प्रकार जून 2022 में एनडीए में प्रवेश लेने वाली महिलाओं की संख्या 19 होगी। उन्होंने कहा कि आश्चर्य की बात है कि 22 दिसंबर 2021 को यूपीएससी द्वारा एनडीए-द्य 2022 परीक्षा के लिए जारी नोटिस में जिसकी परीक्षा 10 अप्रैल 2022 का होनी है कुल 400 प्रवेश लेने हैं, उसमें सेना के लिए 208 (10 महिलाएं सहित), नौसेना के लिए 42 (तीन महिलाएं सहित) और वायुसेना के लिए फ्लाइंग में दो महिला उम्मीदवार सहित 92, ग्रांउड ड्यूटी (तकनीकी) में दो महिला उम्मीदवार सहित 18, ग्राउंड ड्यूटी (गैर तकनीकी) दो महिला उम्मीदवार सहित 10 सीटों पर प्रवेश की जानकारी दी गई है और प्रवेश जनवरी 2023 में दिया जाएगा। शर्मा ने कहा कि 22 दिसंबर 2021 को जारी नोटिस को पढ़कर लगता है कि जनवरी 2023 में भी महिलाओं की सीट 19 से अधिक नहीं होगी। उन्होंने कहा, पहली बार उल्लेख किया गया है कि नौसेना अकादमी में केवल 30 पुरुष उम्मीदवारों को ही प्रवेश दिया जाएगा। यह पाबंदी मनमाना है।